



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 809]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940

No. 809]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

का.आ. 940(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और सहज रीति से प्रत्यक्ष रूप में उनकी हकदारियों को प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार की उपयोगिता से किसी के पहचान को साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रदान करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" (पीएम-किसान) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है जिसका उद्देश्य प्रत्याशित आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और समुचित उपज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की अनुपूर्ति है। यह स्कीम विद्यमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार छोटे और सीमांत भू-जोत कृषि परिवारों को जिनके पास दो हेक्टेयर तक के कृषि योग्य भू-जोत हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है), के लिए प्रतिवर्ष 6000/रु. (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) की दर पर आय सहायता उपलब्ध करवाती है;

और पूर्वोक्त स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) द्वारा किया जाता है;

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्बलित है;

अतः केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित की अपेक्षा करता है, यथा:

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी पात्र लाभार्थी से आधार संख्या या आधार अधिप्रमाणन कराने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।
- (2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी पात्र लाभार्थी, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को आधार संख्या के लिए आवेदन करना होगा परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) का दौरा कर सकते हैं।
- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग से लाभार्थियों जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, के लिए आधार नामांकन की सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुक या तहसील में स्थित कोई आधार नामांकन केन्द्र नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रीकरण के समन्वयन में या स्वयं को यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनाते हुए सुलभ स्थानों में आधार नामांकन की सुविधा प्रदान करेगा:

परन्तु व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी: -

- (क) यदि उसने अपना नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; तथा
- (ख) (i) बैंक पासबुक या फोटो सहित पोस्ट ऑफिस पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) मनरेगा जाँच कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) राजकीय लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति का फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; या (x) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जाँच उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित एक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा जिससे लाभार्थियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. सभी मामलों में, जहां आधार प्रमाणीकरण लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित अपवाद हैंडलिंग तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: -

- (क) फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईआरआईएस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, जिसके द्वारा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय सहज तरीके से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ आईआरआईएस स्कैनर या चेहरा अधिप्रमाणन की व्यवस्था करेगा;

- (ख) उंगलियों के निशान या आईआरआईएस या चेहरे अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल न होने की स्थिति में जहां कहीं संभव और स्वीकार्य हो यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या सीमित समय वैधता के साथ समय आधारित वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;
- (ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या ओटीपी या टीओटीपी अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां वास्तविक आधार पत्र, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है, के आधार पर प्रसुविधा प्रदान की जा सकेगी। राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर क्यूआर कोड रीडर उपलब्ध करवाई जाएगी;

4. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 1-1/2019-किसान कल्याण अनुभाग]

विवेक अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

S.O. 940(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering "Pradhan Mantri Kisan SAMman Nidhi (PM-KISAN)" (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme which aims to supplement the financial needs of farmers in procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields, commensurate with the anticipated income. The Scheme provides income support at the rate of Rs 6,000 per annum (hereinafter referred to as the benefits) to small and marginal landholder farmer families, having cultivable landholding up to two hectares (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme is implemented through the State Government, Union territory Administration and by the Ministry (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby requires the following, namely:-

1. (1) Any eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he or

she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration or the Ministry, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration or the Ministry shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

- (a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; and
- (b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) MGNREGS Job Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:—

- (a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or Face Authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the State Government or the Union territory Administration or the Ministry shall make provisions for IRIS scanners or Face Authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case of biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) In all other cases where biometric or OTP or TOTP authentication is not possible, benefit may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. The necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the State Government or the Union territory Administration or the Ministry;

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the State of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No.1-1/2019-Farmers Welfare Section]

VIVEK AGGARWAL, Jt. Secy.